श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य यहां नहीं थे, यही प्रश्न उन के पीछे बैठने वाले माननीय सदस्य ने किया था ।

श्री शिव नारायण : इन्होंने ऐश्योरेंस दिया था इस हाउस के अन्दर, टी० टी० कृष्णामचारी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्हों ने कोई व्यक्तिगत आश्वासन नहीं दिया था, सरकार की तरफ से दिया था । हमारे सामने कठिनाइयां आयीं, युद्ध हुआ, लेकिन हम पूरे तौर से सतर्क हैं कि उस जिले के लिये क्या करना चाहिये । मुझे मालूम है कि बलिया जिला एक देश भक्त जिला है, वहां से देश भक्त निकले हैं, देश सेवा करने वाले निकले हैं, और इस समय उस जिले के लोग बहुत दूर दूर जा कर देश का काम कर रहे हैं । इसलिये हम सब का कर्तव्य है कि हम उन की सहायता करें ।

Some Hon. Members *rose*–

MR. SPEAKER : There are still 20 or 30 members who want to ask questions. We have already spent half an hour on this. I do not know how I can satisfy everybody. After all, the demands pertaining to planning will be coming up and the hon. members can speak at that time.

Now I go to the next Question. Mr. Kanwar Lal Gupta.

राष्ट्रीय आय और औद्योगिक उत्पादन संबंधी लक्ष्य

*724. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय और औद्योगिक उत्पादन के लिए नियत किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा ये लक्ष्य कहां तक प्राप्त किए गए हैं; और

(ख) लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण क्या हैं ?

उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) और (ख). "चौथी पंचवर्षीय योजना-प्रारंभिक रूपरेखा 1966" में पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है । इसके अलावा, दूसरी तथा तीसरी योजना दस्तावेज तथा समय समय पर जो विभिन्न समीक्षाएं प्रकाशित की गई हैं उनमें योजनाओं की प्रगति दर्शायी गई है । चौथी योजना के प्रारूप की रूपरेखा के अध्याय 1 और 14 की ओर विशेष रूप से और सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में अंकित अन्य प्रकाशनों की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

विवरण

"राष्ट्रीय आय और औद्योगिक उत्पादन संबंधी" श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा दिनांक 26 मार्च, 1969 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 724 के उत्तर में सभापटल पर रखा गया विवरण ।

1. **पहली पंचवर्षीय योजना**

1. पहली पंचवर्षीय योजना–प्रगति प्रतिवेदन 1951-52 और 1952-53 (1953)
2. पहली पंचवर्षीय योजना-प्रगति प्रतिवेदन 1953-54 (1954)
3. पहली पंचवर्षीय योजना-प्रगति प्रतिवेदन अप्रैल-सितम्बर, 1954 (1955)
4. पहली पंचवर्षीय योजना-प्रगति प्रतिवेदन 1954-555 (1956)
5. **पहली पंचवर्षीय योजना की समीक्षा (1957)**

2. **दूसरी पंचवर्षीय योजना**

1. दूसरी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज

2. दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन तथा संभावनाएं (1958)

3. दूसरी पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन : एक सार (1958)

4. दूसरी पंचवर्षीय योजना-प्रगति प्रतिवेदन, 1958-59 (1960)

5. दूसरी पंचवर्षीय योजना-प्रगति प्रतिवेदन 1959-60 (1962)

3. **तीसरी पंचवर्षीय योजना**

1. तीसरी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज

2. तीसरी पंचवर्षीय योजना--प्रगति प्रतिवेदन 1961-62 (1963)

3. तीसरी पंचवर्षीय योजना--मध्यावधि मूल्यांकन (1963)

4. तीसरी योजना प्रगति प्रतिवेदन 1963-65

5. चौथी पंचवर्षीय योजना--प्रारंभिक रूपरेखा

4. **तीन पंचवर्षीय योजनाएं एक साथ**

1. चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभिक रूपरेखा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि एक स्कूल का टीचर जिस प्रकार बच्चों को किताबें पढ़ाकर हुक्का पीने लगता है उसी तरह से 16 किताबों का रेफ़रेंस इस जवाब में दिया गया है। मैं ने सवाल पूछा था।

"the details of the targets fixed for the national income and industrial production."

दो बातों के बारे में मैं ने पूछा था कि क्या-क्या टारगेट थे और कितने कितने पूरे हुए। इतने लम्बे चौडे जवाब की जरूरत नहीं हैं। इन्हों ने तो किताबों को रेफ़रेंस दे दिया। तो जो मेरा सवाल था कि क्या क्या टार्गेट थे, क्या क्या पूरे हुए, क्यों नहीं पूरे हुए, इस का जवाब दें तो मैं आगे सवाल करूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : किताबें अगर पढ़ना है तो जवाब देने की क्या जरूरत है।

श्री ब० रा० भगत : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा का यह नियम है कि जो पब्लिश्ड डाकुमेंट्स हैं उन के बारे में ऐसा विवरण हम दे सकते हैं। यह कहते हैं कि टार्गेट क्या थे और वे कहां तक प्राप्त किये गये और अगर नहीं किये गये तो उस के क्या कारण हैं। इन सब की सूचना दीजिये। तो यह एक लम्बा विवरण देना होगा। इसलिये जनरल सवाल का जनरल जवाब दिया। माननीय सदस्य स्पेसिफिक सवाल पूछें तो उस का स्पेसिफिक जवाब दूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा सवाल यह था नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्शन का क्या टार्गेट था। साथ में यह भी था कि अगर पूरा नहीं हुआ तो क्यों पूरा नहीं हुआ।

श्री ब० रा० भगत : फर्स्ट प्लैन में नेशनल इनकम का टार्गेट था 12 प्रतिशत ग्रोथ का, ऐचीवमेंट हुआ 18.4 प्रतिशत, सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में टार्गेट ग्रोथ का था 25 प्रतिशत और ऐचीवमेंट हुआ 21.5 प्रतिशत, थर्ड फाइव इअर प्लैन में ग्रोथ का टार्गेट था 30 प्रतिशत और ऐचीवमेंट हुआ 15.2 प्रतिशत।

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रोडक्शन भी तो बतलाइये।

श्री ब० रा० भगत : 1966-67 में नेशनल इनकम की ग्रोथ हुई 2 प्रतिशत, 1967-68 में नेशनल इनकम की ग्रोथ हुई 8.9 प्रतिशत। फर्स्ट प्लैन में प्रोडक्शन....

SHRI R. D. BHANDARE : This is general information. This is avilable in the books.

MR. SPEAKER : If the information is available in the published books, you do not ask a question.

श्री ब० रा० भगत : फर्स्ट प्लैन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा 25.1 प्रतिशत, सेकेन्ड प्लैन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा 41.7 प्रतिशत, थर्ड प्लैन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा 44.2 प्रतिशत। Over 16 years industrial production has increased by 165.7%.

श्री कंवर लाल गुप्त : रीजन्स तो बतलाइये।

MR. SPEAKER : If you do not want to ask a question, I will go to the next question.

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि थर्ड प्लैन के एक्स्पेन्सेज जो तय किये गये थे उन से ज्यादा खर्च किया गया और टार्गेट जो थे वह पूरे नहीं हुए। इसका कारण यह है कि उन की प्लैन फाल्टी थी, प्रायारिटी ठीक नहीं थीं, ग्रोवर-ऐम्बिशस प्लैन थी, करप्ट मशीनरी थी और कोई क्लिग्रर कट ग्राजेक्टिव नहीं था। इस के अलावा आप को मालूम है कि जो आदमी रूरल एरियाज में रहते हैं उन में से 5 प्रतिशत केवल 6 रु० महीना खर्च करते हैं। आज 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन को रोटी नहीं मिलती। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह जो प्लैन आगे बनाने वाले हैं उस में वह किसी नैशनलमिनिमम इनकम की गारन्टी देंगे, और कोई फिजिकल टार्गेट होगा, जिस में हर एक आदमी को रोटी मिले या पीने का पानी मिले ?

श्री ब० रा० भगत : जो कुछ माननीय सदस्य ने बतलाया है वह मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इस बीच में हिन्दुस्तान आगे बढ़ा है। यह बात जरूर है कि दिक्कतें हमारे सामने आई हैं, हम जो प्रगति करना चाहते थे उस में बीच बीच में रुकावटें आई हैं, लेकिन आज देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अगर आदमी आंख बन्द कर के न देखे तो मालूम हो सकता है, माननीय सदस्य भी देखेंगे तो पता चलेगा कि देश आगे बढ़ा है और हमारी योजना सफलीभूत हो रही है। हां, यह बात सही है कि बहुत से क्षेत्रों में गरीबी है, यह बात भी सही है कि जो सब से गरीब लोग हैं उन की आमदनी भी कम है और खर्च भी कम है, पीने का पानी गांवों में बहुत नहीं है। यह बात भी सही है कि जो लोगों की कम से कम जरूरतें हैं उन के लिये हम ऐसी योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन को नेशनल मिनिमम इनकम मिले, उन की गरीबी दूर हो सके और इन बातों को हम आगे बढ़ा सकें।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस सरकार ने तीनो पंचवर्षीय योजनाओं में इस बात की कोशिश की कि मोनोपोलीज खत्म हो, लेकिन आज 63 प्रतिशत खेती पर काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो 5 एकड़ या उस से नीचे के मालिक हैं और 11 प्रतिशत ऐसे हैं जो कि लैंडलार्ड हैं जिन के पास 70 प्रतिशत से ज्यादा भूमि है। सरकार ने पंच-वर्षीय योजना में जो खर्च किया है उस में 80 परसेंट तो इन 11 परसेंट लोगों पर किया है और 20 परसेंट 89 परसेंट लोगों पर किया है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज के बारे में मोनोपोली कमिशन की रिपोर्ट है कि 75 परिवार ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के 45 परसेंट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। मंत्री महोदय ने प्लैन में जो कुछ तय किया था उस का नतीजा कुछ और निकला। मैं जानना चाहता हूं कि मोनोपोली खत्म हो और छोटे लोगों तक उस का लाभ पहुंचे, उस के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि मोनोपोली को खत्म करने के लिये हम को जोरदार कदम उठाना चाहिये। जो मोनोपोलीज बिल आया है वह इसी रास्ते पर एक कदम है जहां तक अरबन क्षेत्र का सवाल है इंडस्ट्रियल पालिसी और एकानमिक पालिसी इसी आधार पर है कि मोनोपोली बनने के बाद खत्म न हो साथ साथ कंसेंट्रेशन भी न बढ़े। इसी लिये हमारा डिस्पर्सल का प्रोग्राम है। जहां तक हमारी एकानमिक फोर्सेज का सवाल है हमारी सभी नीतियों का यही आब्जेक्टिव है। जब इंडस्ट्रीज बढ़ती है तब कंसेंट्रेशन भी बढ़ता है, इसलिए सोशल आब्जेक्टिव के कारण दूसरी चीजों को भी लाना पड़ता है और इस के लिये हम सजग हैं। जहां तक रूरल क्षेत्र का सवाल है, यह बात हम को मालूम है कि 5 एकड़ या उस से कम वाले किसान ज्यादा हैं।

श्री शिव नारायण : विकेन्द्रीकरण के बारे में आप का क्या कहना है ?

श्री ब० रा भगत : विकेन्द्रीकरण करने की हमारी नीति है और हम चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण हो।

खेती के बारे में समस्या कुछ ज्यादा उठ खड़ी हुई है क्योंकि अच्छे पैमाने पर पानी, खाद या बीज का इन्तजाम करना है। गांवों में जो अच्छे किसान हैं, बड़े किसान हैं उन को फायदा ज्यादा होता है, साथ साथ गांवों में सोशल और पोलिटिकल कांशसनेस ज्यादा बढ़ रही है इस लिये हमें चाहिये कि हम लोग अपनी योजनाओं में ड्राई फार्मिंग एरिया में छोटे किसानों के लिये और दूसरे लैंडलेस लोगों के लिये ऐसी नीति बनायें जिस से उन की आमदनी बढ़े और उनको मदद कर के हम आगे बढ़ा सकें।

श्री सीताराम केसरी : आर्थिक मोनोपोली और इंडस्ट्रियल मोनोपोली की जो बात है, उस के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कहा कि छोटे छोटे उद्योग धन्धों और छोटे किसानों के लिये ऐसा होना चाहिये कि वह तरक्की करें। मैं जानना चाहता हूँ कि इस को मद्दे नजर रखते हुए कि कभी कभी व्यक्तियों की मोनोपोली ज्यादा हो जाती है, क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी घोषणा करेंगे कि राष्ट्रीय आय का इस सीमा से ज्यादा अंश किसी के पास नहीं होना चाहिये ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक सजेशन है और इस पर भी विचार होता रहता है।

SHRI LOBO PRABHU : As the Minister must be aware, while the financial targets of the three plans have been maintained the physical targets have not been maintained. The reason for this may be, first, there was an under-estimate of the cost of the projects. Secondly, there was inflation. Thirdly, there was bad implementation. I would like to ask a specific question. I want to know whether the Planning Commission, the Chairman of the Planning Commission is also present here, has compared these deficiencies. What conclusions have they arrived at so that in the fourth plan the same mistakes are not repeated ?

SHRI B. R. BHAGAT : Based on our experience we have to prepare the fourth plan. We will try to get over all the deficiencies that the hon. Member has mentioned.

श्री तुलशी दास जाधव : इस देश में जिन लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है उन को फर्स्ट प्लैन, सेकेन्ड प्लैन और थर्ड प्लैन में गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है, जैसे कि देहात के लोग हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन्तजाम किया गया है जिस से सिक्योरिटी न होने पर भी वह अपना उत्पादन बढ़ा सकें, जैसे भैंस रखना है, गाय रखना है ?

श्री ब०रा० भगत: यह बात सही है कि अभी जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है उस में कर्ज उन्हें ही मिलता है जिन की कोई सिक्योरिटी है, बैंक क्रेडिट है या कोआपरेटिव क्रेडिट है वह उन को ही मिलता है जो अच्छे किसान हैं। यह

कमी है हमारे कर्ज के सिस्टम में और हम इस विचार में लगे हुए हैं कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाये ।

श्री मधु लिमये : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि राष्ट्रीय आमदनी और औद्योगिक पैदावार में जो इजाफा हुआ है उसके साथ साथ राष्ट्रीय आमदनी का जो बटवारा होता है, क्या उस में असमानता और गैर बराबरी बढ़ती नहीं जा रही है ? महलनोबीस कमेटी की रपट आपके सामने है, नैशनल सैम्पल की सर्वे की रिपोर्ट आपके सामने है । औद्योगिक पैदावार के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमीरों के उपभोग की जो चीजें होती हैं जैसे एयर कंडीशनर वगैरह हैं उनकी पैदावार तो बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन साधारण जनता के उपभोग में जो चीजें आती हैं उनकी पैदावार उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है । मैं जानना चाहता हूँ कि चौथी योजना में सरकार कौन सी नीतियां अपनाने वाली है जिससे यह गैर बराबरी कम हो ?

श्री जार्ज फरनेंडीस : छोटी मोटर कार ।

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना में इन बातों का खयाल किया जाएगा कि जहां तक सम्भव हो यह कमी दूर हो...

श्री मधु लिमये : कौन सी नीति अपनाने जा रहे हैं....

श्री ब० रा० भगत : योजना आपके सामने आएगी और उस पर बहस भी होगा । तब इसका आपको पता चल जाएगा । आम तौर से यह सही है कि जो लग्जरी गुड्ज हैं उनका उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उन पर कर भी बढ़ रहा है । उन पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है ताकि जो उनका उपभोग करें उनकी बिक्री से सरकार को आमदनी भी हो । जो आम जनता की जरूरत की चीजें हैं जैसे अनाज है या कपड़ा है या और भी दूसरी चीजें हैं उनका उत्पादन बढ़ाने में ज्यादा नेशनल रिसोर्सिस लगें, इसकी कोशिश की जाएगी ।

श्री रणधीर सिंह : मुल्क की आमदनी तभी बढ़ी हुई मैं समझूंगा जब देहात वालों की आमदनी बढ़ेगी जहां पर कि अस्सी फी सदी लोग रहते हैं । जब इस अस्सी फी आबादी की आमदनी बढ़ेगी तभी मुल्क की आमदनी भी बढ़ी है, ऐसा मैं समझूंगा । आज देखने में आता है कि जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, मनतें हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वे सब शहरों में लग रही हैं । जरूरत इस बात की है कि छोटे कारखाने, काटेज इंडस्ट्रीज, कल पुर्जों के रूप में देहातों में खोले जायें । मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की वाजे पालिस क्या है । क्या वह शहरों के बजाय देहातों में छोटे छोटे कारखाने खोलना चाहती है ताकि गांव का जो हरिजन है, जो बैकवर्ड क्लासिस के लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको काम मिले और आबादी का सारा बोझ खेत पर ही न पड़ जाए ? क्या इस तरह से वहां जो बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए सरकार चौथी योजना में कुछ व्यवस्था करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना में विकेन्द्रीयकरण हो, इंडस्ट्रीज का डिसपर्सल गावों की तरफ हो और वे बडे कसबों की तरफ जायें, इस पर ध्यान दिया जाएगा ।

SHRI S. KUNDU : The hon. Minister said that in the First Five Year Plan the target of national income which was fixed was exceeded. At thes ame he time also said that in the Third Five Year Plan the target that was fixed was reduced to half. May I know whether he has made any study of this and, if so, whether he can inform the House if it is not true that during the corresponding period some countries in Asia and like Japan had a steady rise of national income per year at 11 per cent in some years; and if that is so, why during this corresponding period our target fixed was reduced by half ?

SHRI B. R. BHAGAT : I discussed this matter with a leading, top economist in Japan and said that more than economic factors, the sub-conscious factors are responsible for this rise and the sub-conscious factors are discipline, patriotism, dedication and hard work. If we have these....*(interruptions)*.

श्री जार्ज फारनेंडीस : आप में से किसी में भी नहीं है। जहां शर्म लगनी चाहिये वहां आप हस रहे हैं।

SHRI BEDABRATA BARUA : In addition to the factors that have been mentioned by the Hon. Minister, is it not a fact that so far as targets of industrial production are concerned, they are bound to fall short if the plant and machinery are not utilised to their full capacity ? Yesterday, we were surprised to learn from the Industries Minister that the demand position or the order placed on the public enterprises is not very clear. Therefore, may I know from the Hon. Minister whether this has been provided for in the Fourth Plan that the capacity that has been created for heavy machinery will be utilised and if not whether he will make a categorical and definite provision for utilisation of the capacity for heavy machinery production ?

SHRI B. R. BHAGAT : The utilisation of the surplus or unutilised capacity in the industrial sector is the first charge on the national budget. This strategy has been accepted in the Fourth Plan.

श्री स० मो० बनर्जी : राष्ट्रीय आमदनी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है यह ठीक है। लेकिन लोगों की हालत सुधरी नहीं है। इस वास्ते जो सवाल हमसे लोग किया करते हैं अकसर वही सवाल मैं आप से पूछना चाहता हूं। हम से यह सवाल वे करते हैं :

जिस देश में गंगा बहती है उस
देश का पौधा सूखा क्यों ?
जो देश है वीर जवानों का उस
देश का बचपन बूढ़ा क्यों ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा वितरण हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ है, यह हमें मालूम है।

Working of Textile Mills taken over by the Textile Corporation of India

*727. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the number of cotton textile mills taken over by the Textile Corporation of India;

(b) the total number of workers working in these mills;

(c) the terms and conditions under which the mills have been taken over;

(d) whether there has been any improvement in the profitability of these mills since the Corporation took them over; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) to (c). The New Maneckchock Spinning and Weaving Mills Ltd., Ahmedabad was taken over by the Government in February, 1969. The Gujarat State Textile Corporation, which has been appointed as Authorised Controller, will be assisted by the National Textile Corporation in the running of the mill. The number of workers in the mill is about 1700.

(d) and (e). It is too early to make any assessment.

श्री जार्ज फरनेंडीस : इस वक्त अस्सी मिलें जिनमें करीब अस्सी हजार कर्मचारी काम करते हैं बन्द पड़ी हैं। पिछले पांच बरसों से ये मिलें बन्द हैं। चूंकि वे बन्द हुई इस वास्ते इस सदन में और इस सदन के बाहर भी आवाज उठी थी और उसी का यह नतीजा था कि टेक्सटाइल कारपोरेशन की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को एक विधेयक लाना पड़ा। मन्त्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि सिर्फ